

[2023] 1 एस. सी. आर. 335

बाँबी

वी.

केरल राज्य

(2009 की आपराधिक अपील सं. 1439)

12 जनवरी, 2023

[बी. आर. गवई और एम. एम. सुंदरेश, जे. जे.]

साक्ष्य अधिनियम, 1872। 27 - तथ्य की खोज-आपराधिक मुकदमा-तीन आरोपी-कथित रूप से किए गए प्रकटीकरण बयान

अभियुक्त नं. 3 - अपीलार्थी-शिकायतकर्ता के पति के मृत शरीर की बरामदगी-साक्ष्य की प्रशंसा-आयोजित: एस. 27 में यह अपेक्षा की गई है कि खोजा गया तथ्य उस स्थान को शामिल करता है जहाँ से वस्तु का उत्पादन किया गया है और इसके बारे में अभियुक्त का ज्ञान है, और दी गई जानकारी उक्त तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित होनी चाहिए-पिछले उपयोगकर्ता के बारे में जानकारी, या उत्पादित वस्तु का पिछला इतिहास संबंधित नहीं है।

इसकी खोज के लिए-यदि दी गई जानकारी के परिणामस्वरूप वास्तव में कोई तथ्य सामने आता है, तो कुछ गारंटी दी जाती है कि जानकारी सही थी और इसके परिणामस्वरूप उक्त जानकारी को सुरक्षित रूप से साक्ष्य में दिए जाने की अनुमति दी जा सकती है। एस. 27-वर्तमान मामले में, वसूली पंचनामा के अनुसार नहीं है

कथित आवश्यकता, और यह भी कि अभियुक्त सं। 3 अपीलार्थी ने यू/दर्ज किया धारा 27-नतीजतन, अभियोजन पक्ष इस परिस्थिति को साबित करने में विफल रहा कि मृतक का शव आरोपी संख्या 3-अपीलार्थी-आई. पी. सी.-एस. के कहने पर बरामद किया गया था। 395 , 364 , 365 , 380 , 201 , 302 और 303 आर/डब्ल्यू एस। 34 .

साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 27-आयोजित आवेदन: एस के प्रावधान। 27 वे इस दृष्टिकोण पर आधारित हैं कि यदि वास्तव में एक तथ्य की खोज की जाती है

साक्ष्य अंतिम बार देखा गया सिद्धांत-चर्चा-आयोजित: अंतिम बार देखा गया सिद्धांत लागू होता है जहां उस समय के बीच का समय अंतराल जब आरोपी और मृतक को आखिरी बार जीवित देखा गया था और जब मृतक मृत पाया जाता है, इतना कम होता है कि किसी भी व्यक्ति की संभावना कम होती है। अभियुक्त के अलावा अपराध का लेखक बन जाता है

[2023] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

असंभव-यदि अंतिम बार देखे गए समय और मृत पाए गए व्यक्ति के बीच का अंतर लंबा है, तो बीच में किसी अन्य व्यक्ति के आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

आपराधिक मुकदमा-हत्या का मामला-मामला पूरी तरह से चालू है

परिस्थितिजन्य साक्ष्य-परिस्थितिजन्य साक्ष्य की प्रशंसा

- तथ्यों पर, अभियुक्त के खिलाफ एकमात्र परिस्थिति यह थी कि वह

साक्ष्य के आधार पर अंतिम बार मृतक के साथ देखा गया था

अभियोगकारी परिस्थितियां जो अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती हैं- विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, जिससे अपीलार्थी को दोषी ठहराया जाता है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय की पुष्टि की जाती है, तदनुसार, खारिज कर दिया जाता है-अपीलार्थी को बरी कर दिया जाता है - आईपीसी-एसएस। 395 , 364 , 365 , 380 , 201 , 302 और 303 आर/डब्ल्यू एस। 34 .

साक्ष्य-परिवेशीय साक्ष्य-की प्रशंसा

-

किसी मामले में दोषसिद्धि के संबंध में सुनहरे सिद्धांत
आपराधिक मुकदमे पर।

पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य-चर्चा-

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने
पकड़ना: 1. अभियोजन पक्ष के लिए यह आवश्यक है कि

जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है

'साबित किया जा सकता है' और 'साबित किया जाना चाहिए' के बीच कानूनी अंतर। इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात् वे किसी अन्य परिकल्पना पर समझाने योग्य नहीं होने चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी हैं। परिस्थितियाँ ऐसी होनी चाहिए कि वे साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर कर दें। होना ही चाहिए।

सबूतों की एक श्रृंखला इतनी पूर्ण है कि कोई भी उचित नहीं छोड़ता है

अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए आधार और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में अधिनियम

अभियुक्त द्वारा किया गया होगा। [पैरा 10]

2. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के लिए आवश्यक है कि तथ्य

खोज में उस स्थान को शामिल किया गया है जहाँ से वस्तु का उत्पादन किया जाता है और इसके बारे में अभियुक्त का ज्ञान, और जानकारी BOBY VI

केरल राज्य

दिए गए तथ्य का स्पष्ट रूप से उक्त तथ्य से संबंध होना चाहिए। उत्पादित वस्तु के पिछले उपयोगकर्ता, या पिछले इतिहास के बारे में जानकारी इसकी खोज से संबंधित नहीं है। कानून आई. ओ. से साक्ष्य की धारा 27 के तहत विचार के अनुसार खोज पंचनामा तैयार करने की उम्मीद करता है। एक्ट करें। वर्तमान मामले में, वसूली पंचनामे को उपरोक्त आवश्यकता के अनुसार होने के अलावा, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अभियुक्त संख्या 3/अपीलार्थी का कोई बयान दर्ज नहीं है। इसलिए, अभियोजन पक्ष इस परिस्थिति को साबित करने में विफल रहा है कि मृतक का शव आरोपी संख्या 3/अपीलार्थी के कहने पर बरामद किया गया था।

[पैरा 21,26]

3. जहां तक अभियुक्त संख्या 1 का संबंध है, निचली अदालत द्वारा अतिरिक्त परिस्थितियों पर भरोसा करने की मांग की गई और

उच्च न्यायालय कुदाल की कथित बरामदगी है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कुदाल भी उसी स्थान से बरामद किया गया था जहाँ से आरोपी संख्या 3/अपीलार्थी के कहने पर मृतक का शव कथित रूप से बरामद किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने फिर से अभिनिर्धारित किया कि जिस स्थान से कुदाल बरामद किया गया था, वह अभियुक्त संख्या 3/अपीलार्थी के प्रकटीकरण बयान से पहले से ही ज्ञात था; हालाँकि, इसने अभी भी उक्त कुदाल की बरामदगी को साक्ष्य में स्वीकार्य माना। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त वसूली

वह एक ऐसे स्थान से था जो पहले से ही ज्ञात था और विशेष रूप से अभियुक्त संख्या 1 की जानकारी में नहीं था। इसलिए, निचली अदालत ने इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने में फिर से विकृति दिखाई है। [पैरा 28]

4. यह स्पष्ट है कि एकमात्र परिस्थिति जो अब बनी हुई है, वह है अभियुक्त की परिस्थिति जो आखिरी बार उसकी संगति में देखी गई थी।

पीडब्लू1 के साक्ष्य के आधार पर मृतक। हालांकि, केवल अंतिम देखे गए सिद्धांत के आधार पर, दोषसिद्धि दर्ज नहीं की जा सकती थी। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है कि मृतक के शव की बरामदगी मौके पर हुई थी

अभियुक्त सं. 3/अपीलार्थी। अभियुक्त सं. 3/अपीलार्थी के घर से वस्तुओं की बरामदगी, निचली अदालत के अनुसार भी, प्रहसन और मनगढ़ंत है। अभियुक्त नं. 1 के कहने पर कुदाल की बरामदगी एक ऐसे स्थान से हुई है, जिसे निचली अदालत के अनुसार भी प्रकटीकरण बयान के कारण जाना जाता था। अभियुक्त सं. 3/अपीलार्थी द्वारा किया गया। इसलिए अभियोजन पक्ष के पास [2023] 1 एस. सी. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दोषपूर्ण परिस्थितियों की श्रृंखला को साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा जो आरोप के अपराध के अलावा कोई अन्य निष्कर्ष नहीं निकालता है [पैरा 29,30]

शरद बर्डिचंद सारदा बनाम। महाराष्ट्र राज्य
(1984) 4 एससीसी 116: [1985] 1 एससीआर 88; यू. पी. राज्य बनाम

सतीश (2005) 3 एससीसी 114: [2005] 1 एससीआर 1132;

चंद्रन बनाम. तमिलनाडु राज्य (1978) 4 एससीसी 90

: [1979] 1 एस. सी. आर. 176; कर्नाटक राज्य बनाम। डेविड

रोजारियो एंड अदर (2002) 7 एस. सी. सी. 728: [2002] 2
पूरक। एस. सी. आर. 419 और सुब्रमण्य बनाम। कर्नाटक राज्य

2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1400 पर भरोसा किया। -
सुरेश चंद्र बहरी बनाम। बिहार राज्य 1995 सप. (1)

एस. सी. सी. 80 [1994] 1 पूरक। एस. सी. आर. 483-संदर्भित।

पुलुकुरी कोटय्या और अन्य बनाम। राजा-सम्राट 1946

एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. सी. 47-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1994] 1 पूरक। एससीआर 483

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

[1985] 1 एससीआर 88

उस पर भरोसा करें

पैरा 9

[2005] 1 एससीआर 1132

उस पर भरोसा करें

पैरा 16

[1979] 1 एससीआर 176

उस पर भरोसा करें

पैरा 22

[2002] 2 पूरक। एससीआर 419

उस पर भरोसा करें

पैरा 24

आपराधिक अपील

न्यायनिर्णय: आपराधिक ऐप

2009 का सं. 1439।

उच्च निगम के 25.08.2008 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2005 के सी. आर. एल. ए. No.326 में केरल के एनर्कुलम में।

आर. बसंत, सीनियर एड. , अब्दुल्ला नसीह वी. टी., मीना के. पॉल

अक्षय, अशोक बसोया, सुश्री श्रुति जोस, पी. एस. सुधीर, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

के. एन. बालगोपाल, वरिष्ठ अधिवक्ता। , हर्षद वी. हमीद, दिलीप पूलक

सुश्री एशली हर्षद, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

बाँबी वी. केरल राज्य

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था
बी. आर. गवई, जे.

1. यह अपील उच्च न्यायालय की विद्वत खंड पीठ द्वारा पारित 25 अगस्त 2008 के फैसले और आदेश को चुनौती देती है। केरल, एर्नाकुलम में (इसके बाद "उच्च न्यायालय" के रूप में संदर्भित) आपराधिक अपील सं. 326 , 230 और 2005 का 847 इस प्रकार शिवू @शिवू सिंह (अभियुक्त संख्या 1) और बाँबी (अभियुक्त संख्या 3/अपीलार्थी) द्वारा दायर अपीलों को खारिज करते हुए, इस प्रकार अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा पारित 18 दिसंबर 2004 के दोषसिद्धि और सजा के फैसले को बरकरार रखते हुए।

सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट-II (तदर्थ अदालत), त्रिशूर (इसके बाद "ट्रायल कोर्ट" के रूप में संदर्भित) 2003 के सत्र मामले संख्या 208 में

उक्त अभियुक्त व्यक्तियों का सम्मान। उसी विवादित फैसले के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने, हालांकि, बीजू @बाबी (आरोपी संख्या 2) द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया।

2. विवरणों से कटा हुआ, वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं

इसके अंतर्गत: 2.1 21 नवंबर, 2000 को, लीला डब्ल्यू/ओ विश्वनाथन (शिकायतकर्ता/पीडब्लू-1) ने पुलिस स्टेशन, अंतिक्काडु, जिला के समक्ष एक बयान दिया। त्रिशूर, जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसके पति विश्वनाथन (मृतक) का छोटा भाई शिवू उर्फ शिवू सिंह (आरोपी नंबर 1) एक दोषी था, जो उस समय जेल से गुजर रहा था क्योंकि वह चोरी के कई मामलों में शामिल था, जिसमें उक्त चोरी से चोरी की गई वस्तुओं का उसके पति द्वारा निपटारा किया गया था।

2.2 शिकायतकर्ता का मामला है कि शिवू उर्फ शिवू सिंह (आरोपी नंबर 1) जेल से भाग गया था और फरार था। इस डर से कि विश्वनाथन (मृतक) जेल से भागने के बारे में पुलिस को खुलासा करेगा, शिवू उर्फ शिवू सिंह (आरोपी नंबर 1) अन्य आरोपी व्यक्तियों, अर्थात् आरोपी नंबर 2 से आरोपी नंबर 7, के साथ दोपहर 20.11.2000 पर विश्वनाथन (मृतक) के घर एक जीप में आया। इसके बाद आरोपी व्यक्तियों ने विश्वनाथन (मृतक) को चाकू की नोक पर पकड़ लिया, जबर्न उसके मुंह में शराब डाल दी और उसे तब तक पीने के लिए मजबूर किया जब तक कि वह बेहोश नहीं हो जाता। जब लीला (शिकायतकर्ता/पीडब्लू-1) ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो आरोपी व्यक्तियों द्वारा ले जाए गए चाकू के कारण उसकी हथेली पर चोटें आईं, जिससे उन्होंने उस पर वार करने का प्रयास किया। इसके बाद, लीला (शिकायतकर्ता/पीडब्लू-1) को उसके पति के साथ आंखों पर पट्टी बांधकर जीप में ले जाया गया। लगभग [2023] 1 एस. सी. आर. की दूरी तय करने के बाद

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सूचना रिपोर्ट (एक्स. पी-19) (संक्षेप में, "एफ. आई. आर".) उपरोक्त अभियुक्त व्यक्तियों के साथ-साथ अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया। भारतीय संविधान की धारा 395 और 365 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए व्यक्ति

दंड संहिता, 1860 (इसके बाद आई. पी. सी. के रूप में संदर्भित)।

पी-23), विश्वनाथन का शव, जिसे भरतपुड़ा नदी के तट पर पट्टिथारा में दफनाया गया था, बरामद किया गया था। इसके अतिरिक्त, आरोपी संख्या 3 के घर से चोरी का सामान भी बरामद किया गया और उसे अतिरिक्त के रूप में चिह्नित किया गया। पी-14। शिवू @शिवू सिंह (आरोपी नंबर 1) और वीजू @ बाबू (आरोपी नंबर 2) को 28 नवंबर 2000 को गुरुवायूर पुलिस ने गुरुवायूर के एक लॉज से गिरफ्तार किया था। इसके बाद, उन्हें 2 दिसंबर 2000 को अंतिक्काडु पुलिस को सौंप दिया गया। के आधार पर

शिवू @शिवू सिंह (आरोपी नंबर 1) का खुलासा बयान, जिस कुदाल से मृतक के दफन स्थल को खोदा गया था, उस स्थान के पास बरामद किया गया था जहां से शव को निकाला गया था, एक प्लास्टिक बैग में छुपाया गया था।

2.4 जाँच के समापन पर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, न्यायालय-II, त्रिशूर के समक्ष एक आरोप पत्र दायर किया गया, जो

2.5 निचली अदालत द्वारा आई. पी. सी. की धारा 395, 364, 365, 380 और धारा 34 के साथ पठित दंडनीय अपराधों के लिए आरोप तय किए गए। 2.6 सभी अभियुक्तों ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया और मुकदमा चलाने का दावा किया। अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त व्यक्तियों के अपराध को घर लाने के लिए 33 गवाहों से पूछताछ की। अभियोजन पक्ष ने 14 सामग्री वस्तुओं को भी अभिलेख पर रखा जिन्हें एम. ओ. 1 से एम. ओ. 14 के रूप में चिह्नित किया गया था। बचाव पक्ष की ओर से जिरह के दौरान मृतक के पिता शेखरन (डी. डब्ल्यू.-1) से पूछताछ की गई। अभियुक्त व्यक्तियों से BOBY v के तहत पूछताछ की गई।

केरल राज्य [बी. आर. गवई, जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 (संक्षेप में, "आई. डी. 1".) जिसमें उन्होंने उन परिस्थितियों से इनकार किया जो उनके खिलाफ साक्ष्य में दिखाई दीं जो उनके सामने रखी गई थीं। मुकदमे के समापन पर, विद्वत निचली अदालत ने शिबू उर्फ शिबू सिंह (आरोपी नंबर 1), बीजू उर्फ बाबू (आरोपी नंबर 2) और बाँबी (आरोपी नंबर 3/अपीलार्थी) को आरोपित अपराधों का दोषी पाया और तदनुसार उन्हें आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसने उन्हें आगे कड़ी कार्रवाई से गुजरने का निर्देश दिया।

आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 364, 395 और 201 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए विभिन्न अवधियों के लिए कारावास। सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया था।

2.7 इससे व्यथित होकर, नोस पर आरोप लगाया। 1 3 ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी-अपनी अपीलें को प्राथमिकता दी। उच्च न्यायालय द्वारा विवादित फैसले में शिबू @शिबू सिंह (आरोपी नंबर 1) और बाँबी (आरोपी नंबर 3/अपीलकर्ता) द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया गया, लेकिन बीजू @बाबू (आरोपी) द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए खुशी हुई।

नं. 2), जिससे जहां तक बीजू @बाबू (अभियुक्त नं. 2) का संबंध है, निचली अदालत के दोषसिद्धि और सजा के फैसले को दरकिनार कर दिया गया।

3. इससे व्यथित होने के कारण, वर्तमान अपील।

4. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री आर. बसंत और प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री के. एन. बालगोपाल-केरल राज्य को सुना है।

5. श्री बसंत, विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करेंगे कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों ने दोषसिद्धि और सजा देने में गलती की है अपीलार्थी-आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 395, 365, 364, 201, 380, 302 और 302 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए बाँबी। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के खिलाफ अपना मामला साबित करने में विफल रहा है।

बाँबी उचित संदेह से परे है और अभियोजन पक्ष के मामले में स्पष्ट खामियां हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने भी पाया कि मुकदमे के दौरान जिन अभियोजन पक्ष के गवाहों से पूछताछ की गई थी, उनके बयानों में विसंगतियां थीं। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने बीजू @बाबू (अभियुक्त संख्या 2) के संबंध में शिकायतकर्ता/पीडब्लू-1 के बयान में स्पष्ट विसंगतियों का भी अवलोकन किया, जिसके आधार पर उच्च न्यायालय ने उक्त अभियुक्त बीजू @बाबू (अभियुक्त संख्या 2) को उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया।

23] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. श्री बसंत ने प्रस्तुत किया कि पुलिस के समक्ष दिए गए बयानों के आधार पर एक आरोपी व्यक्ति के कहने पर शुरू की गई वसूली के मामलों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 (इसके बाद "साक्ष्य अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत एक ज्ञापन की आवश्यकता है। यह है।

प्रस्तुत किया कि, तत्काल मामले में रिकॉर्ड पर साक्ष्य के अवलोकन पर, न तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत ऐसा ज्ञापन मृतक के शव की बरामदगी के समय तैयार किया गया था विश्वनाथन, न ही स्वतंत्र या पंच गवाहों के हस्ताक्षर थे

उक्त पुनर्प्राप्ति के समय लिया गया। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यह जांच अधिकारी (संक्षेप में, 'आई. ओ. ') का कर्तव्य था कि वह बॉबी (अपीलार्थी) से प्राप्त जानकारी पर कार्रवाई करते हुए उक्त ज्ञापन तैयार करे और आई. ओ. की ओर से इस तरह की निष्क्रियता अभियोजन मामले को दूषित कर देगी, कम से कम जहां तक मृतक के शव की बरामदगी को साबित करने का संबंध है।

इस मामले में परिस्थितियों की श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि एक अभियुक्त व्यक्ति की दोषसिद्धि को केवल अंतिम देखे गए सिद्धांत को साबित करने के आधार पर कायम नहीं रखा जा सकता है क्योंकि इसे गवाहों के बयानों के साथ पुष्टि करने की आवश्यकता थी जिनकी सुनवाई के दौरान जाँच की जाती है और साथ ही रिकॉर्ड में रखे गए अन्य साक्ष्य भी। अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में विसंगतियों की ओर इशारा करते हुए, जिन पर नीचे की अदालतों द्वारा भरोसा किया गया था, यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि को अकेले उक्त आधार पर कायम नहीं रखा जा सकता है। 8. इसके विपरीत, श्री बालगोपाल प्रस्तुत करते हैं कि निचली अदालतों ने साथ-साथ अभियुक्त व्यक्तियों को अपराधों का दोषी पाया है

आरोप लगाया। अभियोजन पक्ष ने दोषपूर्ण परिस्थितियों को उचित संदेह से परे साबित किया है। इसने उन परिस्थितियों की श्रृंखला को भी साबित किया है जो अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य निष्कर्ष पर नहीं पहुँचती हैं। वह सुरेश चंद्र बहरी बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भर करता है। बिहार राज्य 1.

9. निर्विवाद रूप से, वर्तमान मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। शरद के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ

बर्डहिचंद सारदा बनाम। महाराष्ट्र राज्य 2 ने एक ऐसे मामले में दोषसिद्धि के संबंध में सुनहरे सिद्धांत निर्धारित किए हैं जो पूरी तरह से

1 1995 सप. (1) एससीसी 80

2 2 (1984) 4 एस. सी. सी. 116 बॉबी बनाम।

केरल राज्य [बी. आर. गवई, जे.]

पर्याप्त सबूत। हम लाभप्रद रूप से उक्त मामले में इस न्यायालय के निम्नलिखित प्रस्तावों का उल्लेख कर सकते हैं:

" 153. इस निर्णय के गहन विश्लेषण से पता चलता है कि

एक के खिलाफ एक मामले से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए

अभियुक्त को पूरी तरह से स्थापित कहा जा सकता है:

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए।

यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया कि

संबंधित परिस्थितियाँ "होनी चाहिए या होनी चाहिए" और "नहीं" स्थापित की जा सकती हैं। "साबित किया जा सकता है" और "होना चाहिए या साबित किया जाना चाहिए" के बीच न केवल एक व्याकरणिक बल्कि एक कानूनी अंतर है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम में अभिनिर्धारित किया गया था। की स्थिति

महाराष्ट्र [(1973) 2 एससीसी 793: 1973 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 1033: 1973 सी. आर. एल. एल. जे. 1783] जहाँ अवलोकन किए गए थे: [एससीसी पैरा 19,

पी। 807 : एस. सी. सी. (सी. आर. आई) पी. 1047]

" निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को

और न केवल एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले दोषी हो सकता है और 'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के बीच की मानसिक दूरी लंबी है और कुछ निष्कर्षों से अस्पष्ट अनुमानों को विभाजित करती है।

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात्, वे किसी अन्य परिकल्पना पर समझाने योग्य नहीं होने चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त

दोषी है,

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए और

प्रवृत्ति,

(4) उन्हें एक को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए

सिद्ध करने के लिए और (5) सबूतों की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूरी हो कि छोड़ न जाए

के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार

अभियुक्त की निर्दोषता और यह दिखाना चाहिए कि सभी मनुष्यों में अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

संभावना है कि यह कार्य

10. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि यह आवश्यक है कि वे परिस्थितियाँ जिनसे [2023] 1 एस. सी. आर. का समापन हुआ।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपराध को पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। अदालत का मानना है कि यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अदालत द्वारा आरोपी को दोषी ठहराए जाने से पहले आरोपी 'होना चाहिए' और न कि केवल 'दोषी हो सकता है'। यह माना गया है कि वहाँ

यह न केवल एक व्याकरणिक है, बल्कि 'साबित किया जा सकता है' और 'होना चाहिए' या साबित किया जाना चाहिए' के बीच एक कानूनी अंतर है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात् वे किसी अन्य परिकल्पना पर स्पष्टीकरण योग्य नहीं होने चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है। यह आगे माना गया है कि परिस्थितियाँ ऐसी होनी चाहिए कि वे हर संभावित परिकल्पना को बाहर कर दें सिवाय इसके कि

साबित करने के लिए। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि साक्ष्य की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े। अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होना चाहिए।

11. इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के आलोक में, हमें जांच करनी होगी

वर्तमान मामला।

12. निचली अदालत ने निम्नलिखित परिस्थितियों पर भरोसा किया है:

अंतिम बार मृतक के साथ देखा गया;

(1)

(

(ख)

अभियुक्त नंबर 3-बाँबी;

आरोपी नंबर 1 से कुदाल की बरामदगी-शिवू @शिवू

(iii)

सिंह;

((iv) अभियुक्त सं. के कहने पर शव की बरामदगी।

3 - बाँबी;

13. निचली अदालत ने आरोपी संख्या को दोषी ठहराया था। 1 खोजने पर 3 तक

कि अभियोजन पक्ष ने उपरोक्त परिस्थितियों को साबित कर दिया था उन्हें। अपील में, उच्च न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष बीजू @बाबी (आरोपी संख्या 2) के खिलाफ मामले को साबित करने में विफल रहा और तदनुसार उसे बरी कर दिया।

14. हालांकि उच्च न्यायालय की विद्वत खंड पीठ ने पाया कि अभियोजन पक्ष मामले को उचित से परे साबित करने में विफल रहा है

जहाँ तक अभियुक्त सं. 2 का संबंध है, संदेह ने अभिनिर्धारित किया कि, जहाँ तक अभियुक्त सं. 1 और 3 संबंधित थे, अभियोजन पक्ष ने मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया था।

बॉबी वी. केरल राज्य [बी. आर. गवई, जे.]

15. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने पाया कि अभियुक्त व्यक्तियों की परिस्थिति अंतिम थी।

के साक्ष्य के आधार पर मृतक की कंपनी में देखा गया

संबंधित, शव और गहने की बरामदगी के संबंध में एक अतिरिक्त सबूत था। जहाँ तक शिबू @शिबू सिंह की बात है (अभियुक्त नं. 1) चिंतित था, उच्च न्यायालय ने पाया कि वसूली

कुदाल का उपयोग उस दफन स्थल को खोदने के लिए किया गया था जहां शव को छुपाया गया था, एक अतिरिक्त परिस्थिति थी जो शिबू @शिबू सिंह (आरोपी नंबर 1) के अपराध को साबित करती थी।

16. जहां तक अंतिम देखे गए सिद्धांत का संबंध है, राज्य के मामले में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा।

यू. पी. वी. सतीश 3:

" 22. अंतिम बार देखा गया सिद्धांत तब लागू होता है जब उस समय के बीच का समय-अंतराल जब आरोपी और मृतक को आखिरी बार जीवित देखा गया था और जब मृतक मृत पाया जाता है।

इससे कम कि अभियुक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के अपराध के लेखक होने की संभावना असंभव हो जाती है। कुछ मामलों में यह सकारात्मक रूप से स्थापित करना मुश्किल होगा कि मृतक अंतिम था।

अन्य सकारात्मक साक्ष्य यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि अभियुक्त और मृतकों को आखिरी बार एक साथ देखा गया था, यह आना खतरनाक होगा

उन मामलों में अपराध के निष्कर्ष तक। इस मामले में सकारात्मक सबूत है कि मृतक और आरोपी को एक साथ देखा गया था गवाहों द्वारा पीडब्लू 3 और 5, पीडब्लू 2 के साक्ष्य के अलावा।

17. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि अंतिम बार देखा गया सिद्धांत लागू होता है जहां उस समय के बीच का अंतराल-जब आरोपी और मृतक को आखिरी बार जीवित देखा गया था और जब मृतक मृत पाया जाता है-इतना कम होता है कि आरोपी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के अपराध का लेखक होने की संभावना असंभव हो जाती है। अगर बीच का अंतर

अंतिम बार देखे जाने और मृत पाए जाने का समय लंबा है, तो बीच में किसी अन्य व्यक्ति के आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। 3 3 (2005) 3 एस. सी. सी 114 [2023] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

18. वर्तमान मामले में, शिकायतकर्ता/पीडब्लू-1 के अनुसार,

मनालूर कदवु, वह उस स्थान पर गया और उसे दोपहर 02.00 पर गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि उनके कबूलनामे के आधार पर उनके घर से विभिन्न सामान जब्त किए गए थे। उन्होंने आगे कहा कि उसके बाद उसी दिन, आरोपी उन्हें भरतपुड़ा में उस स्थान की ओर ले गए जहाँ मृतक को दफनाया गया। उन्होंने कहा कि, ढीली मिट्टी को देखने के बाद, दृश्य को संरक्षित किया गया था क्योंकि यह एक अजीब समय था। उन्होंने आगे कहा कि 26 नवंबर 2000 को, आरोपी नंबर 3 के नेतृत्व में, वे उस स्थान पर पहुंचे और तहसीलदार, ओट्टापलम ने जांच रिपोर्ट तैयार की।

19. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि सबसे पहले, उस तारीख से कम से कम पांच दिनों का अंतराल है जिस दिन, पीडब्लू-1 के अनुसार, मृतक था

अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा ले जाया गया और शव बरामद किया गया। हालांकि, महत्वपूर्ण सवाल यह होगा कि क्या यह माना जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे स्थापित किया था कि शव की बरामदगी बाँबी (आरोपी संख्या 3/अपीलार्थी) के कहने पर हुई थी। केवल उस स्थिति में जब अभियोजन पक्ष यह स्थापित करता है कि शव की बरामदगी बाँबी (आरोपी संख्या 3/अपीलार्थी) के कहने पर हुई थी, तो पाँच दिनों के अंतराल की प्रासंगिकता आएगी।

20. 1946 की शुरुआत में, प्रिवी काउंसिल ने विचार किया था

पुलुकुरी कोटय्या और अन्य के मामले में साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रावधान। राजा-सम्राट। उक्त मामले में प्रिवी काउंसिल की निम्नलिखित टिप्पणियों को संदर्भित करना प्रासंगिक होगा:

" दूसरा प्रश्न, जिसमें S का निर्माण शामिल है। 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर अब विचार किया जाएगा। वह खंड और दो पूर्ववर्ती खंड, जिनके साथ इसे पढ़ा जाना चाहिए, इन शब्दों में हैं। [उनके प्रभु ने एस. एस. पढ़ा। 25 , 26 और साक्ष्य अधिनियम के 27 और जारी रखा:] धारा 27, जो कलात्मक रूप से शब्दबद्ध नहीं है, पूर्ववर्ती धारा द्वारा लगाए गए निषेध के लिए एक अपवाद प्रदान करती है, और पुलिस में किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए कुछ बयानों को सक्षम बनाती है।

4 1946 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. सी. 47 बाँबी वी.

केरल राज्य [बी. आर. गवई, जे.]

अभिरक्षा साबित करने के लिए। खंड को संचालन में लाने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि इसके परिणामस्वरूप एक तथ्य की खोज एक पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी को अपदस्थ किया जाना चाहिए, और उस पर इतनी जानकारी जो इस तरह से खोजे गए तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित है, साबित की जा सकती है। यह खंड इस दृष्टिकोण पर आधारित प्रतीत होता है कि यदि वास्तव में इसके परिणामस्वरूप एक तथ्य की खोज की जाती है

दी गई जानकारी, कुछ गारंटी दी जाती है जिससे कि जानकारी सही थी, और तदनुसार सुरक्षित रूप से साक्ष्य में दी जा सकती है; लेकिन स्पष्ट रूप से जानकारी की सीमा

स्वीकार्य तथ्य की सटीक प्रकृति पर निर्भर होना चाहिए जिससे ऐसी जानकारी का संबंध होना आवश्यक है। आम तौर पर इस धारा को तब लागू किया जाता है जब पुलिस हिरासत में कोई व्यक्ति छिपाने के किसी स्थान से कोई वस्तु पेश करता है, जैसे कि मृत वस्तु। शरीर, एक हथियार या आभूषण, जिसे अपराध से जुड़ा हुआ कहा जाता है

जिसमें सूचना देने वाला आरोपी है। क्राउन के लिए श्री मेगाँ,

उन्होंने तर्क दिया है कि ऐसे मामले में "तथ्य की खोज" उत्पन्न भौतिक वस्तु है, और यह कि कोई भी जानकारी जो उस वस्तु से स्पष्ट रूप से संबंधित है, उसे साबित किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण पर किसी व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी कि शव उसके द्वारा हत्या किए गए व्यक्ति का है, कि उत्पादित हथियार वह है जिसका उपयोग उसने हत्या में किया था, या कि उत्पादित गहने डकैती में चोरी हो गए थे, सभी स्वीकार्य होंगे। यदि यह एस का प्रभाव है। 27 , पुलिस के सामने या पुलिस हिरासत में व्यक्तियों द्वारा किए गए इकबालिया बयानों पर पिछली दो धाराओं द्वारा लगाए गए प्रतिबंध में बहुत कम सार रहेगा। यह प्रतिबंध संभवतः विधायिका के इस डर से प्रेरित था कि पुलिस के प्रभाव में एक व्यक्ति को अनुचित दबाव के प्रयोग से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। लेकिन अगर सब कुछ

जो प्रतिबंध हटाने के लिए आवश्यक है कि बाद में प्रस्तुत किए गए किसी उद्देश्य से संबंधित जानकारी के स्वीकारोक्ति में शामिल किया जाए, यह मान लेना उचित लगता है कि पुलिस की प्रेरक शक्तियां अवसर के बराबर साबित होंगी, और व्यवहार में प्रतिबंध अपना प्रभाव खो देगा। निर्माण के सामान्य सिद्धांतों पर उनके

लॉर्डशिप्स सोचते हैं कि एस के लिए परंतु। 26 , एस द्वारा जोड़ा गया। 27 , धारा के सार को रद्द करने के लिए नहीं माना जाना चाहिए। उनसे

लॉर्डशिप्स का मानना है कि खंड के भीतर "खोजे गए तथ्य" को उत्पादित वस्तु के बराबर मानना गलत है; खोजा गया तथ्य उस स्थान को गले लगाता है जहाँ से वस्तु [2023] 1 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रस्तुत किया गया और अभियुक्त को इस बारे में जानकारी दी गई, और

दी गई जानकारी का इससे स्पष्ट संबंध होना चाहिए।

तथ्य। पिछले उपयोगकर्ता, या पिछले इतिहास के बारे में जानकारी

उत्पादित वस्तु में सेटिंग में इसकी खोज से संबंधित नहीं है जिसकी खोज की गई है। हिरासत में किसी व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी

कि "मैं अपने घर की छत में छुपा कर एक चाकू लाऊंगा"

चाकू की खोज नहीं होती है; चाकू की खोज की गई थी

कई साल पहले। इससे इस तथ्य की खोज होती है कि एक चाकू

सूचना देने वाले के घर में उसकी जानकारी के लिए छिपा दिया जाता है, और यदि

चाकू का उपयोग आयोग में किया गया साबित होता है

अपराध, पाया गया तथ्य बहुत प्रासंगिक है। लेकिन अगर बयान के लिए

जिन शब्दों को जोड़ा जाए "जिनके साथ मैंने ए को चाकू मारा", ये शब्द हैं

अस्वीकार्य क्योंकि वे चाकू की खोज से संबंधित नहीं हैं सूचना देने वाले के घर में।

[जोर दिया

गया]

21. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27

यह आवश्यक है कि खोजा गया तथ्य उस स्थान को गले लगाता है जहाँ से उद्देश्य प्रस्तुत किया जाता है और इसके बारे में अभियुक्त का ज्ञान होता है, और दी गई जानकारी स्पष्ट रूप से उक्त तथ्य से संबंधित होनी चाहिए। इसकी जानकारी

पिछले उपयोगकर्ता के रूप में, या उत्पादित वस्तु का पिछला इतिहास, इसकी खोज से संबंधित नहीं है। उक्त दृष्टिकोण का इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में लगातार पालन किया गया है।

22. यह न्यायालय, चंद्रन बनाम के मामले में। तमिल राज्य

नाडू', की वसूली के साक्ष्य पर विचार करने का अवसर मिला

अभियुक्त नं. 1 के बयान के अभिलेख के अभाव में दोषारोपण करने वाले लेख। उक्त मामले में भी, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत आरोपी नंबर 1 का कोई बयान दर्ज नहीं किया गया था जिससे गहने बरामद हुए।

न्यायालय ने पाया कि सत्र न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की थी कि इकबालिया बयान (उदा. पी-27) जो पीडब्लू-34 से पहले दर्ज किया गया था। निम्नलिखित का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा।

उक्त मामले में इस न्यायालय की टिप्पणियां:

" 36. इस प्रकार तथ्य यह है कि कोई इकबालिया बयान नहीं

ए-1 के कारण इन रत्नों की वसूली के तहत साबित किया गया था धारा 27, साक्ष्य अधिनियम "।

5 (1978) 4 एस. सी. सी. 90 बॉबी वी.

केरल राज्य [बी. आर. गवई, जे.]

23. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने वसूली पर भरोसा करने से इनकार कर दिया

क्योंकि अभियुक्त का कोई इकबालिया बयान साबित नहीं हुआ था

आर साक्ष्य अधिनियम की धारा 27।

24. कर्नाटक राज्य बनाम के मामले में न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा। डेविड रोजारियो और

उसे।

" 5 यह जानकारी जो अन्यथा स्वीकार्य है, धारा 27 के तहत अस्वीकार्य हो जाती है यदि जानकारी किसी पुलिस अधिकारी की हिरासत में किसी व्यक्ति से नहीं आई थी या किसी ऐसे व्यक्ति से आई थी जो किसी पुलिस अधिकारी की हिरासत में नहीं था। बयान जो

धारा 27 के तहत स्वीकार्य वह जानकारी है जो खोज की ओर ले जाती है। इस प्रकार, जो स्वीकार्य है

सूचना, वही साबित करना होगा न कि पुलिस अधिकारी द्वारा उस पर बनाई गई राय। दूसरे शब्दों में, हिरासत में रहते हुए अभियुक्त द्वारा दी गई सटीक जानकारी जिससे वस्तुओं की बरामदगी हुई, उसे साबित करना होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि

अभियुक्त और अभियोजन पक्ष दोनों का लाभ कि दी गई जानकारी को दर्ज और साबित किया जाना चाहिए और यदि नहीं

इस प्रकार अभिलिखित, सटीक जानकारी साक्ष्य के माध्यम से प्रस्तुत की जानी चाहिए। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में अंतर्निहित मूल विचार बाद की घटनाओं द्वारा पुष्टि का सिद्धांत है। यह सिद्धांत इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि कोई तथ्य है

किसी के बल पर की गई खोज के रूप में खोजा गया एक कैदी से प्राप्त जानकारी, ऐसी खोज एक है

इस बात की गारंटी दें कि कैदी द्वारा दी गई जानकारी

इस व्याख्या का समर्थन करते हुए कि खंड में परिकल्पित "तथ्य की खोज" उस स्थान को शामिल करता है जहाँ से वस्तु का उत्पादन किया गया था, अभियुक्त का इसके बारे में ज्ञान, लेकिन जानकारी दिया गया उस प्रभाव से स्पष्ट रूप से संबंधित होना चाहिए। (देखें स्थिति

728 [2023] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

महाराष्ट्र

वी. दामू [(2000) 6 एस. सी. सी 269: 2000 एससीसी (सीआरआई)

1088

: 2000 क्रि एल. जे. 2301] "।

[जोर दिया गया]

25. इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने हाल ही में
अमान्या वी। कर्नाटक राज्य ने इस प्रकार देखा है:

" 82. उपरोक्त साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, हम आगे बढ़ते हैं
विचार करें कि क्या अभियोजन पक्ष साबित करने में सक्षम रहा है और
कानून के अनुसार खोजों को स्थापित करें। की धारा 27
साक्ष्य अधिनियम इस प्रकार है:

" 27. अभियुक्त से कितनी जानकारी प्राप्त हो सकती है
साबित किया जाए।

बशर्ते कि, जब किसी तथ्य को अपदस्थ कर दिया जाता है जैसा कि पता चला है
किसी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप
किसी भी अपराध का अभियुक्त, एक पुलिस अधिकारी की हिरासत में,
इस तरह की जानकारी का इतना, क्या यह एक
स्वीकारोक्ति या नहीं, जैसा कि स्पष्ट रूप से इस तथ्य से संबंधित है
खोजा गया, साबित किया जा सकता है। "

83. सभी के साक्ष्य में पहली और बुनियादी दुर्बलता

उपरोक्त अभियोजन पक्ष के गवाह यह हैं कि उनमें से किसी ने भी गवाही नहीं दी है

अपीलार्थी द्वारा यहाँ दिया गया सटीक बयान
खोज हुई

जिसके परिणामस्वरूप अंततः एक प्रासंगिक तथ्य की

साक्ष्य अधिनियम की धारा 27।

84. यदि जाँच अधिकारी का कहना है कि अभियुक्त अपीलार्थी

अपनी स्वतंत्र इच्छा और इच्छा पर हिरासत में रहते हुए एक बयान दिया

कि वह उस स्थान पर ले जाएगा जहाँ उसने हथियार छिपाए थे

अपराध का स्थान, शव को दफनाने का स्थान, कपड़े आदि।

पहला काम जो जाँच अधिकारी को करना चाहिए था वह था
बुलाना।

थाने में ही दो स्वतंत्र गवाहों को

एक बार दो स्वतंत्र गवाह पुलिस के पास पहुंचेंगे।

अपराध आदि। जब अभियुक्त हिरासत में रहते हुए ऐसा करता है
(पंच-गवाह)

दो स्वतंत्र गवाहों के समक्ष बयान

एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1400 बॉबी बनाम।

केरल राज्य [बी. आर. गवई, जे.]

अभियुक्त द्वारा दिए गए सटीक कथन या सटीक शब्दों को पंचनामे के पहले भाग में शामिल किया जाना चाहिए जो जाँच अधिकारी कानून के अनुसार निकाल सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के उद्देश्य से पंचनामे का यह पहला भाग हमेशा स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में पुलिस स्टेशन में तैयार किया जाता है ताकि विश्वास दिलाया जा सके।

कि अभियुक्त द्वारा अपनी स्वतंत्र इच्छा और उस स्थान को इंगित करने की इच्छा व्यक्त करते हुए एक विशेष बयान दिया गया था जहाँ अपराध के लिए इस्तेमाल किया गया हथियार या कोई अन्य वस्तु छिपी हुई थी। एक बार पंचनामे का पहला भाग पूरा हो जाने के बाद पुलिस दल आरोपी और दो स्वतंत्र गवाहों (पंच गवाह) के साथ उस विशेष स्थान पर आगे बढ़ेगा जिसका नेतृत्व आरोपी कर सकता है। यदि उस विशेष स्थान से अपराध का हथियार या खून से सने कपड़े या कोई अन्य वस्तु है

तब पता चला कि पूरी प्रक्रिया का वह हिस्सा पंचनामे का दूसरा भाग बनेगा। इस तरह कानून जांच अधिकारी से खोज पंचनामा बनाने की उम्मीद करता है साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत विचार किया गया। अगर हम पढ़ते हैं

मामला "।

26.

इस न्यायालय ने विस्तार से विचार किया है कि कानून कैसे उम्मीद करता है

आई. ओ. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत विचार के अनुसार खोज पंचनामा तैयार करेगा। वर्तमान मामले में, वसूली को एक तरफ छोड़ दें।

पंचनामा उपरोक्त आवश्यकता के अनुसार होने के कारण, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत बाँबी (आरोपी संख्या 3/अपीलार्थी) का कोई बयान दर्ज नहीं है। इसलिए हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष इस परिस्थिति को साबित करने में विफल रहा है कि मृतक का शव बाँबी के कहने पर बरामद किया गया था। (अभियुक्त सं. 3/अपीलार्थी)।

27. एक अन्य परिस्थिति जिस पर उच्च न्यायालय ने भरोसा किया वह यह थी कि आभूषणों की बरामदगी बाँबी (आरोपी संख्या 3/अपीलार्थी) के कहने पर की गई थी। हम पाते हैं कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों ने इस तरह की वसूली पर भरोसा करने में स्पष्ट रूप से गलती की है। निचली अदालत ने पाया कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री थी कि कथित वसूली

मेमो एक मनगढ़ंत दस्तावेज था और एक्स्ट के अनुसार कथित वसूली थी। पी-14 प्रहसन है। हालाँकि, निचली अदालत ने अभी भी [2023] 1 एस. सी. आर. की उक्त वसूली पर भरोसा किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अभियुक्त को दोषी ठहराएँ। हमारे विचार में, इस संबंध में निचली अदालत का निष्कर्ष पूरी तरह से विकृत है जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने की है।

28. जहाँ तक शिबू @शिबू सिंह (आरोपी संख्या 1) का संबंध है, निचली अदालत द्वारा अतिरिक्त परिस्थितियों पर भरोसा करने की मांग की गई और उच्च न्यायालय कुदाल की कथित वसूली है। यह ध्यान देने योग्य है कि कुदाल भी उसी स्थान से बरामद किया गया था जहाँ से

मृतक का शव कथित तौर पर बरामद किया गया था बाँबी का उदाहरण (अभियुक्त सं. 3/अपीलार्थी)। निचली अदालत ने फिर से कहा कि जिस स्थान से कुदाल बरामद किया गया था, वह पहले से ही बाँबी (आरोपी संख्या 3/अपीलार्थी) के प्रकटीकरण बयान से ज्ञात था।

29. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अब केवल वही परिस्थिति बनी हुई है जो पीडब्लू-1 के साक्ष्य के आधार पर मृतक के साथ आरोपी को आखिरी बार देखी गई थी। मामले के उस दृष्टिकोण में, हम पाते हैं कि केवल अंतिम देखे गए सिद्धांत के आधार पर, दोषसिद्धि दर्ज नहीं की जा सकती थी। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है कि मृतक के शव की बरामदगी बाँबी (आरोपी संख्या 3/अपीलार्थी) के कहने पर की गई थी। निचली अदालत के अनुसार भी बाँबी (आरोपी संख्या 3/अपीलार्थी) के घर से वस्तुओं की बरामदगी प्रहसन और मनगढ़ंत है। शिबू @शिबू सिंह (आरोपी नंबर 1) के कहने पर कुदाल की बरामदगी एक ऐसी जगह से हुई है, जो निचली अदालत के अनुसार भी ज्ञात थी।

बाँबी द्वारा दिया गया प्रकटीकरण बयान (इसमें अभियुक्त संख्या 3/अपीलार्थी)।

30. मामले के उस दृष्टिकोण में, हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष दोषपूर्ण परिस्थितियों की श्रृंखला को साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है जो

अभियुक्त के अपराध के अलावा कोई अन्य निष्कर्ष नहीं निकलता है।

31. जहाँ तक सुरेश चंद्र बहरी (उपरोक्त) के मामले में विद्वान वरिष्ठ वकील श्री बालगोपाल द्वारा रखी गई निर्भरता का संबंध है, यह इस न्यायालय ने कहा है कि यह पूरी तरह से गलत है क्योंकि अनुच्छेद 40 में

इस प्रकार:

" 40. उपरोक्त प्रस्तुतियों के गुण या दोषों पर चर्चा करने से पहले हम यह बताना चाहेंगे कि BOBY v से संबंधित कानून।

केरल राज्य [बी. आर. गवई, जे.]

प्रकृति में केवल परिस्थितिजन्य है तो उस स्थिति में जिन तथ्यों और परिस्थितियों से अभियोजन पक्ष द्वारा अपराध का निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता है, उन्हें सभी उचित संदेह से परे पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए और इस तरह से स्थापित तथ्य और परिस्थितियां न केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होनी चाहिए, बल्कि उन्हें अभियुक्त की निर्दोषता के साथ पूरी तरह से असंगत भी होना चाहिए और सुसंगत हर उचित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए। अपनी मासूमियत के साथ "।

32. उक्त मामले में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना आगे प्रासंगिक होगा:

" 71. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रावधान इस दृष्टिकोण पर आधारित हैं कि यदि कोई तथ्य वास्तव में पाया जाता है

दी गई जानकारी के परिणामस्वरूप, कुछ गारंटी दी जाती है कि जानकारी सही थी और परिणामस्वरूप उक्त जानकारी को साक्ष्य में सुरक्षित रूप से देने की अनुमति दी जा सकती है क्योंकि यदि ऐसी जानकारी को लेखों या अपराध के साधन की खोज से और मजबूत और पुष्टि की जाती है और जिससे यह विश्वास होता है कि अपराध के लेखों के बारे में की गई स्वीकारोक्ति के बारे में जानकारी गलत नहीं हो सकती है।

33. उक्त निर्णय के अनुच्छेद 71 के अवलोकन से पता चलेगा कि न्यायालय ने दोहराया है कि दो आवश्यकताएँ

साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 का अनुप्रयोग यह है कि (1) व्यक्ति

जानकारी देना किसी भी अपराध का आरोपी होना चाहिए और (2) वह पुलिस हिरासत में भी होना चाहिए। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रावधान इस दृष्टिकोण पर आधारित हैं कि यदि कोई तथ्य वास्तव में है

उक्त जानकारी को साक्ष्य में सुरक्षित रूप से दिए जाने की अनुमति दी जा सकती है। 34. उक्त मामले के तथ्यों में, न्यायालय ने पाया कि वास्तव में, अपीलार्थी द्वारा किए गए प्रकटीकरण का एक इकबालिया बयान था

गुरबचन सिंह जिसकी पुष्टि की गई थी

आपत्तिजनक लेख। इस प्रकार, न्यायालय ने प्रकटीकरण कथन और उस ओर से दिए गए साक्ष्य पर विश्वास किया। जैसा कि पहले ही ऊपर कहा जा चुका है, [2023] 1 एस. सी. आर. में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वर्तमान मामले में, मृतक के शव की बरामदगी के संबंध में बाँबी (आरोपी संख्या 3/अपीलार्थी) का कोई इकबालिया बयान दर्ज नहीं है।

35. परिणामस्वरूप, अपील की अनुमति दी जाती है।

36. निचली अदालत द्वारा 18 दिसंबर 2004 को पारित निर्णय, जिससे अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 395, 365, 364, 201, 380, 302 के तहत दोषी ठहराया गया और उच्च न्यायालय द्वारा 25 अगस्त 2008 को पारित किए गए विवादित फैसले को खारिज कर दिया गया। अपीलार्थी को सभी आरोपों से बरी कर दिया जाता है। अभियुक्तक जमानत बॉन्ड खारिज भऽ जायत।

37. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

अपील की अनुमति दी गई।

बिभूति भूषण बोस (सहायक: शेवाली मोंगा, एलसीआरए)